साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 11, अंक : 13 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 29 अक्टूबर 2025 से 4 नवंबर 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

जलवायु परिवर्तन से बदल सकता है अल नीनो का स्वरूप- नई शोध का बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। धरती के बढ़ते तापमान से अल नीनो प्रणाली में बड़ा बदलाव, मौसम के पैटर्न होंगे अधिक नियमित लेकिन चरम प्रभावशाली।

अत्यधिक मौसमीय प्रभाव- बारिश और सूखे के चरम उतार-चढ़ाव और अधिक तीव्र होंगे, कृषि और जल संसाधन प्रभावित होंगे। अत्यधिक मौसमीय प्रभाव- बारिश और सूखे के चरम उतार-चढ़ाव और अधिक तीव्र होंगे, कृषि और जल संसाधन प्रभावित होंगे। अल नीनो की अनियमितता में बदलाव- आने वाले 30 से 40 वर्षों में अल नीनो-ला नीना चक्र अधिक नियमित और शक्तिशाली हो सकता है। समुद्र और वायु का बढ़ता तालमेल- गर्म महासागर और वायुमंडल की परस्पर क्रिया से ईएनएसओ के दोलन की तीव्रता बढ़ेगी। वैश्विक जलवायु प्रणालियों का समन्वय- ईएनएसओ अन्य बड़े जलवायु चक्रों (एनएओ, आईओडी, टीएनए) के साथ तालमेल बिठा सकता है।

अत्यधिक मौसमीय प्रभाव- बारिश और सूखे के चरम उतार-चढ़ाव और अधिक तीव्र होंगे, कृषि और जल संसाधन प्रभावित होंगे। पूर्वानुमान में सुधार लेकिन उच्च जोखिम- नियमित ईएनएसओ से मौसम पूर्वानुमान आसान होगा, लेकिन इसके बढ़ते प्रभावों के लिए तैयारी जरूरी। दुनिया के मौसम और जलवायु पर सबसे अधिक असर डालने वाली प्राकृतिक प्रणालियों में से एक है अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन (ईएनएसओ)। यह प्रणाली प्रशांत महासागर के तापमान और हवा के प्रवाह में होने वाले उतार-चढ़ाव से जुड़ी है और इसका असर भारत के मानसून से लेकर अमेरिका की बारिश तक देखा जाता है। लेकिन एक नई अंतर्राष्ट्रीय शोध से पता चला है कि जैसे-जैसे धरती गर्म होती जा रही है, यह प्रणाली आने वाले दशकों में एक बड़े बदलाव से गुजर सकती है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जर्मनी और आयरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन को प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने उन्नत जलवायु मॉडल का उपयोग करते हुए पाया कि आने वाले 30 से 40 सालों में अल नीनो और ला नीना का मौजूदा अनियमित चक्र एक नियमित और अधिक शक्तिशाली चक्र में बदल सकता है। अत्यधिक मौसमीय प्रभाव- बारिश और सूखे के चरम उतार-चढ़ाव और अधिक तीव्र होंगे, कृषि और जल संसाधन प्रभावित होंगे।

अभी तक अल नीनो हर दो से सात साल में कभी-कभी होता है और उसकी तीव्रता भी अलग-अलग होती है। लेकिन शोध के अनुसार भविष्य में यह प्रणाली लगभग एक घड़ी की तरह नियमित और तीव्र हो सकती है, यानी समुद्र की सतह के तापमान में बड़े बदलाव और उससे जुड़े मौसमीय प्रभाव अधिक पूर्वानुमान योग्य, लेकिन साथ ही अधिक खतरनाक भी हो जाएंगे।

इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण है धरती के बढ़ते तापमान के कारण महासागर और वायुमंडल के बीच बढ़ती परस्पर क्रिया है। जब समुद्र गर्म होता है, तो वह अधिक ऊर्जा वातावरण को देता है, जिससे प्रशांत क्षेत्र में हवाओं और तापमान के बीच एक तरह क तालमेल बनने लगती है। अत्यधिक मौसमीय प्रभाव- बारिश और सूखे के चरम उतार-चढ़ाव और अधिक तीव्र होंगे, कृषि और जल संसाधन प्रभावित होंगे।

यह तालमेल धीरे-धीरे इतनी मजबूत हो सकती है कि अल नीनोङ्कला नीना चक्र खुद से चलने लगे, यानी यह एक प्रकार का जलवायु दोलन बन जाए जो अपनी निश्चित लय में चलता रहे।

शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि एक गर्म दुनिया में उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर एक तरह के जलवायु टिप्पिंग पॉइंट से गुजर सकता है, जहां यह अस्थिर होकर अपने आप में एक नियमित दोलन में बदल जाता है। अत्यधिक मौसमीय प्रभाव- बारिश और सूखे के चरम उतार-चढ़ाव और अधिक तीव्र होंगे, कृषि और जल संसाधन प्रभावित होंगे। शोध में यह भी पाया गया कि भविष्य में अल नीनो केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह अन्य प्रमुख जलवायु प्रणालियों के साथ जुड़ सकता है। इनमें शामिल हैं इसका अर्थ है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की जलवायु प्रणालियां एक ही ताल में चलने लगेंगी, जैसे कई पेंडुलम एक साथ झूलने लगें। इसके कारण कुछ क्षेत्रों में बारिश और सूखे के पैटर्न और भी तीव्र हो सकते हैं। शोध के अनुसार, दक्षिणी कैलिफोर्निया, आइबेरियन प्रायद्वीप (स्पेन- पुर्तगाल) जैसे क्षेत्रों में बारिश में बदलाव संबंधी प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी एक साल भारी बारिश और अगला साल गहरा सूखा। अत्यधिक मौसमीय प्रभाव- बारिश और सूखे के चरम उतार-चढ़ाव और अधिक तीव्र होंगे, कृषि और जल संसाधन प्रभावित होंगे।

इस तरह के अचानक बदलाव कृषि, जल संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकते हैं। भारत जैसे देश, जहां मानसून अल नीनो से गहराई से जुड़ा है, वहां भी इसका अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है।

हालांकि वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि अल नीनो का अधिक नियमित होना मौसमी पूर्वानुमान के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे मौसम की भविष्यवाणी अधिक सटीक हो सकेगी। लेकिन इसके साथ-साथ समाज को अधिक चरम मौसमी घटनाओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा।

इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अल्फ्रेड वेगेनर संस्थान जलवायु मॉडल (ए डब्ल्यूआई-सीएम 3) नामक अत्याधुनिक जलवायु मॉडल का उपयोग किया। यह मॉडल वायुमंडल में 31 किलोमीटर और महासागर में चार से 25 किलोमीटर के संकल्प पर काम करता है, जो जलवायु प्रणालियों की बेहद सूक्ष्म समझ प्रदान करता है।

उन्होंने उच्च उत्सर्जन वाले ग्रीनहाउस गैस परिदृश्य के तहत मॉडल चलाया और वास्तविक अवलोकनों से तुलना की। परिणामों से स्पष्ट हुआ कि कुछ अन्य मॉडल भी इसी प्रकार के बदलाव का संकेत दे रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन नहीं सत्ता परिवर्तन असल मुद्दा!

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने वैश्विक मंच से अपनी एक अहम बात फिर रखी है। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर अपने संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को एक 'बड़ा धोखा' बताया और इससे जुड़े हुए ऐसे सभी लोगों को, जिनमें हम सभी शामिल हैं, धूर्त तक कह दिया है जो वास्तव में इस दिशा में तत्काल कार्रवाई की वकालत करते हैं।

रोष भरे अंदाज में उन्होंने अपने भाषण में यूरोप को हरित ऊर्जा अपनाने के लिए लताड़ा और कहा कि इससे लागत और बढ़ेगी जिससे वृद्धि की रफ्तार कम हो जाएगी। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को खारिज कर दिया और उन्होंने यह तक कह दिया कि कोयला स्वच्छ है। लेकिन मैं आपकी बुद्धिमता को कमतर दिखाने या यह समझाने के लिए ऐसा नहीं लिख रही हूं कि ट्रंप क्यों गलत हैं। हम जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता को जानते हैं क्योंकि चरम स्तर की मौसमी घटनाएं हमारी दुनिया में देखी जा रही हैं जो अपने साथ आर्थिक तबाही और मानवीय त्रासदी ला रही हैं। सवाल यह है कि जब ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बात की तब वह वास्तव में किसे संबोधित कर रहे थे? मेरा मानना है कि हमें इसी पर चर्चा करनी चाहिए। वह उस भव्य कमरे में मौजूद नेताओं से यह बात नहीं कर रहे थे और वह आप या मेरे जैसे लोगों के लिए भी यह बात नहीं कर रहे थे। वह सीधे तौर पर अमीर दुनिया और 'अमीर बनने की कगार पर पहुंचने वाली दुनिया' दोनों में मौजूद बड़ी संख्या में सामान्य, मध्यम और कामकाजी वर्ग के लोगों को संबोधित कर रहे थे, जो मानते हैं कि उन्हें वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में ठगा और वंचित किया गया है।

ट्रंप यह संदेश सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इन सभी के मन में इस बात की मुहर लग जाए कि दरअसल यह समस्या प्रवासियों का बढ़ता हस्तक्षेप है जिनके बारे में उनका यह भी ख्याल है कि वे मूल नागरिकों की आजीविका छीन रहे हैं। उनके मुताबिक कमजोर सरकारें इसे होने दे रही हैं और कोई सजा भी नहीं दे रही हैं और फिर इसे बढ़ती जीवन लागत, घटती वास्तविक मजदूरी और हरित ऊर्जा को अपनाने की लागत से जोड़ा जाता है, जिसके बारे में ट्रंप कहते हैं कि यह पश्चिमी सभ्यता के पतन का कारण बनेगा। पवनचक्की, जो पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में कम लागत पर स्वच्छ बिजली बनाती है, ट्रंप उस पर भी जीवन स्तर को घटाने का आरोप लगता है।

वह चाहते हैं कि यह संदेश पूरी दुनिया में फैले विशेष रूप से पश्चिमी देशों में ताकि लोग 'सनकी वामपंथियों' (उनके शब्द, मेरे नहीं) के खिलाफ हो जाएं। हमें संयुक्त राष्ट्र में उनके संदेश को एक राजनीतिक प्रयास के रूप में देखना चाहिए ताकि लोगों को 'सही दिशा' की ओर मोड़ा जा सके और उन सरकारों से दूर किया जा सके जो सामाजिक न्याय और जलवायु से जुड़े कदमों में भरोसा करती हैं। हमें यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पश्चिमी देशों में गहरा असंतोष है जो मुक्त-व्यापार वैश्वीकरण वाले शासन के वास्तुकार थे और जिन्होंने आर्थिक विकास का नेतृत्व किया।

ट्रंप इसमें और उबाल लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे पश्चिम की राजनीति में बदलाव लाया जा सकें, खासतौर पर कम से कम उन जगहों पर जहां दुनिया में बदलाव की सख्त जरूरत को लेकर प्रतिबद्धता है। वह चाहते हैं कि ऐसी सरकारें विफल हों ताकि बहुपक्षवाद, वैश्विक एकजुटता और जलवायु कार्रवाई के खिलाफ खड़े पक्षों की जीत हो सके। यह एक ऐसे व्यापक पैमाने पर शासन परिवर्तन की बात है जो पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा वास्तव में हो भी रहा है। यूरोप की महत्त्वाकांक्षी जलवायु नीति को गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय आयोग उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के अगले दौर पर समझौते करने में विफल रहा। अब इन नीतियों के प्रति विरोध बढ़ रहा है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन पक्षों की ओर आकर्षण बढ़ा है जो जलवायु परिवर्तन से दूर हटते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि ट्रंप करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति इस आंदोलन को तेज करना चाहते हैं ताकि दुनिया उनके पक्ष में हो जाए। जलवायु परिवर्तन इस राजनीतिक खेल में एक मोहरा बन गया है, जो ऊर्जा के कारोबार और अन्य चीजों में सख्त आर्थिक हितों से प्रेरित है। इसके लिए ट्रंप को जलवायु एजेंडे को 'कट्टर वामपंथी सनकी' लोगों के काम के रूप में दर्जा दिए जाने और उसे खारिज करने की दरकार है। इसका अर्थ यह भी है कि जो कोई भी जलवायु परिवर्तन से पैदा हुए 'अस्तित्व के संकट' जैसी परिस्थितियों को लेकर चिंतित है या यहां तक कि ऊर्जा तंत्र से प्रदूषण खत्म करने की जरूरत पर जोर देता है, वह इस 'जागरूक' ब्रिगेड का हिस्सा है। यह वास्तव में बाकी समाज को एक पक्ष में शामिल होने के लिए मजबूर करता है और ऐसा ही कुछ महामारी के दौरान हुआ था या उस वक्त भी हुआ था जब ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ (ईयू) छोड़ने के लिए मतदान किया था। यह इस मुद्दे को और विषाक्त बनाता है और यह पूरा विमर्श कुलीन वर्ग बनाम अन्य तक केंद्रित हो जाता है। इससे भी खराब बात यह है कि यह विज्ञान और विशेषज्ञों को बदनाम करता है और इन्हें इस तरह से दर्शाया जाता है जैसे ये सामान्य लोगों की कठिन परिस्थितियों या वास्तविकताओं से पूरी तरह अनजान हों। हमें इस तरह की ब्रांडिंग से लड़ना चाहिए क्योंकि यह ट्रंप के अपमानजनक शब्दों से कहीं अधिक नुकसान करता है। उदाहरण के तौर पर, भारत जैसे देशों में हमारे जैसे पर्यावरणविदों की इस तरह की लेबलिंग वास्तव में हमारे संदेशों और काम को कमजोर कर सकती है। जब हमें विकास-विरोधी कहा जाता है तब यह वास्तव में इस तथ्य से ध्यान हटाता है कि पर्यावरण और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही कारण है कि हमने सावधानीपूर्वक और जानबूझकर यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है कि जलवायु-परिवर्तन नीतियां हमारे देशों में विकास की रणनीतियों का हिस्सा हों। हमारे लिए,आर्थिक विकास के लिए ऐसी राह तलाशना समझदारी है जो प्रदूषण के बगैर आएं। हालांकि हम यह भी समझते हैं कि हमारी विभाजित और असमान दुनिया में इस तरह के विचार हमारे साझा घर, हमारे ग्रह पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं इसलिए हम दुनिया को दिए गए इस संबोधन को सिर्फ ट्रंप की एक और बयानबाजी के रूप में खारिज नहीं कर सकते हैं।

सैकड़ों मामले कोर्ट मेंज भू-अर्जन के मामलों में नाम दर्ज न होने की वजह से लिटिगेशन के मामले बढ़े

इंदौर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, मप्र सडक़ विकास निगम की परियोजनाओं के निर्माण के लिए अर्जित भूमि का नामांतरण के बाद राजस्व अभिलेख में नाम अनिवार्य रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में भू-अर्जन की कार्रवाई होने के बाद भी संबंधित विभाग का नाम दर्ज नहीं होता। इस वजह से कालांतर में विभिन्न तरह के विवाद की स्थिति बनी रहती है। कलेक्टरों से कहा गया है कि वह भू अर्जन के बाद तत्काल बाद संबंधित विभागों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराएं। यदि इसमें किसी भी तरह की कोताही पाई गई तो इसके लिए संबंधित जिलों के कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। राज्य शासन की तरफ से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में मप्र के सभी 55 जिलों के कलेक्टरों को राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने का पत्र दिया है।

विभाग ने कहा कि अभी देखने में आया है कि कई कलेक्टर भू-अर्जन के बाद भी दस्तावेजों में संबंधित विभाग का नाम अद्यतन नहीं करते। इस वजह से अवसर विवाद की स्थिति पैदा होती है। इस विवाद की वजह से कई मामले कोर्ट में पेंडिंग है। इस वजह से विभाग का समय अनावश्यक रूप से जाया होता है। विभाग ने कलेक्टरों से कहा कि अपने अधीनस्थ राजस्व अमले को भू अर्जन की कार्रवाई के बाद राजस्व अभिलेख में संबंधित विभाग का नाम दर्ज करने के लिए निर्देशित करें। कलेक्टरों से कहा गया कि विभाग का नाम दर्ज नहीं होने के कारण इसमें भविष्य में किसी भी तरह की विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, मार्ग, रेलवे, रेलवे मप्र सडक़ विकास निगम की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण, उन्नयन के लिए समय-समय पर केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय तथा मप्र शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में निजी भूमि का अर्जन किया जाता है।

इस संबंध में मू अर्जन की कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, रेलवे एक्ट 1989, भू अर्जन पुनर्वासन एवं पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 तथा मप्र की आपसी सहमति क्रय नीति 2014 के तहत मू-अर्जन अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी भू अर्जन के माध्यम से की जाती है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग में 12 हजार 3 बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 17 हजार 49 बिलों का भुगतान नहीं किया ठाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 9 हजार 965 बिलों की 34 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि का बकाया बिल नहीं चुकाया है। स्कूल शिक्षा विभाग को 18 हजार 539 बिलों के 29 करोड़ 64 लाख रुपए चुकाना बाकी है। स्वास्थ्य महकमा भी मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का बकायादार है। उसे 1 हजार 910 बिलों के 21 करोड़ 7 लाख रुपए चुकाना बाकी है। जलसंसाधन विभाग ने ही 497 बिलों के 13 करोड़ 97 लाख रुपए नहीं चुकाए है। गृह विभाग ने 2070 बिजली बिलों के 10 करोड़ 49 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। पीएचई को 445 बिलों के 11. करोड़ 35 लाख रुपए चुकाना है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने 6 करोड़ 87 लाख राजस्व विभाग ने 3 करोड़ 76 लाख रुपए बकाया है। प्रदेश के सोलह सरकारी महकमों पर 72 हजार 900 बिजली बिलों की 406 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि बकाया है। ये महकमें लगातार नोटिसों के बांद भी बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर रहे है सर्वाधिक बकाया राशि नगरीय विकास एवं आवास विभाग पर 125 करोड़ 62 लाख रुपए और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर 102 करोड़ 32 लाख रुपए है। हालांकि वित्त विमाग ने बजट दिया है मगर विभाग भुगतान नहीं कर रहे है।

परमात्मा ने शरीर कर्म के लिए दिया है, सत्कर्मों से समाज की करें सेवा- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव जबलपुर में रोटरी अवार्ड समारोह में हुए शामिल

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि परमात्मा ने हमें शरीर अच्छे कर्मों के लिए दिया है, यदि हमारे कर्म सत्कर्म में बदल जाएं तो समाज का कल्याण हो जाएगा। रोटरी क्लब इसी दिशा में पूरे मनोयोग से कम कर रहा है और समाज को एक नई दिशा दे रहा है, जो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को संस्कारधानी जबलपुर में रोटरी इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त करने वाले रोटेरियन श्री अरुण कांत अग्रवाल एवं श्री संदीप जैन को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव को रोटरी क्लब की मानद सदस्यता प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मां नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है और वह समुद्र में समाहित हो जाती है। मां नर्मदा ने जबलपुर को अद्भुत आशीर्वाद दिया है, इससे जबलपुर का नाम संस्कारधानी पड़ा है। मां नर्मदा के आशीर्वाद से ही जबलपुर का काला पत्थर संगमरमर में बदला जा रहा है यह केवल जबलपुर में ही संभव है। मां नर्मदा के आशीर्वाद से संस्कारधानी जबलपुर को रोटरी क्लब के लिए कार्य करने वाले महान सपूत मिले हैं, जिन्होंने अपने सामाजिक दायित्व और सेवा भाव से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कारधानी जबलपुर का नाम रोशन किया है। रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड पाने वाले श्री अरुण कांत अग्रवाल और श्री संदीप जैन ने जो सेवा भाव दिखाया है वह अनुकरणीय और प्रेरणादायक है। विकास के मामलों में प्रदेश सरकार जन कल्याण की भावना से सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रही है। यह काम रोटरी जैसी संस्था पिछले 120 सालों से कर ली रही है और इसने अपने कर्मों से साबित किया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रोटरी क्लब जबलपुर को जिला एक्सीलेंस अवार्ड मिलने के लिए बधाई दी और कहा कि सेवा के क्षेत्र में रोटरी क्लब इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि रोटरी क्लब निस्वार्थ भाव से सेवा के अनेक प्रकल्पों को जमीन पर उतार रहा है। संस्कारधानी जबलपुर के लिए यह गर्व की बात है कि यहां के दो रोटेरियन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।

नाइट्रस ऑक्साइड मामले में एनजीटी ने कृषि मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 27 अक्टूबर 2025 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा धान के खेतों से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन घटाने के लिए सुझाई गई छह रणनीतियों पर जानकारी मांगी गई है।

ट्रिब्यूनल देश में धान की किस्मों में नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता से जुले मुद्दे की जांच कर रही है। यह जांच इसलिए की जा रही है क्योंकि नाइट्रोजन आधारित उर्वरक ही नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया जैसी गैसों से हवा को, और नाइट्रेट व अमोनियम से पानी को प्रदूषित करते हैं। इसका असर मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर भी पड़ता है। गौरतलब है कि इससे पहले 14 अक्टूबर 2025 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में एक जवाबी हलफनामा दायर किया था। इस हलफनामे में मंत्रालय ने कहा है कि भारत में धान की लोकप्रिय किस्मों में नाइट्रोजन उपयोग की क्षमता को लेकर जो अंतर हैं, वे वास्तविक चिंता का विषय हैं। गौरतलब है कि मंत्रालय ने माना था कि द हिन्दू की नई रिपोर्ट में उठाई गई समस्याएं पूरी तरह वाजिब हैं। जम्मू-कश्मीर में बडगाम जिले की चाडूरा तहसील के वाथूरा गांव में बन रहे रिंग रोड ने एक किसान के बागान को बरबाद कर दिया है। यह सड़क बटपोरा वाथूरा इलाके में जमीन को दो हिस्सों में बांटते हुई निकाली गई है, जिससे सिंचाई का प्राकृतिक जल प्रवाह रुक गया और खेतों में पानी भरने लगा। शिकायतकर्ता गुलाम नबी भट का कहना है कि लगातार जलभराव के कारण उनके छह कनाल में फैले सेब के बागान में सैकड़ों पेड़ सूख गए हैं। यह बात जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति के क्षेत्रीय निदेशक की रिपोर्ट में भी दर्ज है। रिपोर्ट के अनुसार, पहले इस क्षेत्र में सड़क के नीचे से पानी निकलने के लिए क्रॉस ड्रेनेज पाइप लगे थे, लेकिन रिंग रोड के निर्माण के दौरान ये पाइप बंद हो गए। इसकी वजह से बाग में लगातार पानी भरने लगा। निरीक्षण के समय बाग के मालिक गुलाम नबी भट पंप लगाकर पानी निकालते पाए गए। 30 जुलाई 2025 को बडगाम के मुख्य उद्यान अधिकारी द्वारा दाखिल रिपोर्ट में बताया गया कि यह हाई डेंसिटी सेब का बाग 2018 में प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम (पीएमडीपी) के तहत लगाया गया था। बाग छह कनाल क्षेत्र में फैला है और यह इलाका निचली जमीन में स्थित है। जब बाग लगाया गया था, तब विभाग ने पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था की थी ताकि कहीं पानी जमा होकर फसलों को नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए विशेष नालियां बनाई गई थीं ताकि जलभराव की समस्या न हो। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक पेड़ सामान्य रूप से बढ़ रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी भरने और दबाने के कारण ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया। इसकी वजह से बाग में पानी भर गया।

जानकारी दी गई है कि लंबे समय तक पानी भरे रहने से पेड़ों में जड़ों में सड़न की समस्या शुरू हो गई, जिससे करीब 300 पेड़ सूख गए। बाकी पेड़ों की बढ़ोतरी भी रुक गई है, इन पेड़ों में भी पत्तियों के पीलेपन और कमजोर वृद्धि के लक्षण दिख रहे हैं। ड्रेनेज नालियां बंद होने के कारण बाग में गंभीर जलभराव हुआ है, जिससे फलों के पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है।

रिपोर्ट से पता चला है कि बाग में सेब के कुल 955 पेड़ लगे हैं, जिनमें से 300 पेड़ पूरी तरह सूख गए या नष्ट हो गए हैं, यानी करीब 30 फीसदी नुकसान हुआ है। बाकी बचे 695 पेड़ों में से भी ज्यादातर में पत्तियां पीली पड़ गई हैं और उनकी बढ़त रुक गई है। बारिश के दौरान जलभराव के कारण इन पेड़ों में भी करीब 20 से 25 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। इन दोनों रिपोर्टों को जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 13 सितंबर 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दायर किया था, जो इस मामले पर 8 मई 2025 को दिए गए आदेश पर सबमिट की गई हैं।

अब प्रदेश के आठ शहरों में दौड़ेंगी 972 ई-बसें

भोपाल. प्रदेश में अब आठ शहरों में ई-बसों का संचालन किया जाएगा। इनमें से 6 शहर पहले से तय थे लेकिन अब इनमें देवास और सतना को और जोड़ा गया है। इसके साथ इंदौर और भोपाल में ई-बसों की संया बढ़ाई गई है। इन शहरों में सार्वजनिक बस सेवा के तौर पर केवल इलेक्ट्रिक बसें ही चलाने की तैयारी की जा रही है। इस तरह पहले जहां प्रदेश में 582 ई-बसों का संचालन तय था वहीं अब यह संया बढ़कर 972 हो गई है। हालांकि इन बसों का संचालन शुरू होने के लिए अभी अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी बसों की टेंडरिंग प्रक्रिया में 6 से 8 माह लगेंगे।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मध्यप्रदेश के आठ शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, देवास और सतना के लिए 972 ई-बसों के संचालन की मंजूरी दे दी है। पहले इंदौर में 150 और भोपाल में 100 बसों का संचालन तय किया गयास था, लेकिन अब यहां 50-50 बसें और बढ़ा दी गई हैं। प्रदेश में इन बसों का संचालन कई चरणों में शुरू किया जाएगा। हाल ही में प्रदेश में 400 ई-बसों का संचालन शुरू करने के लिए टेंडर खोले गए हैं। जल्द 300 और बसों के लिए टेंडर खोले जाएंगे। शेष बसों के लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया बाद में होगी, जिसमें समय लगेगा। अभी खोले गए टेंडरों में हर बस के संचालन में प्रति किमी 58.40 रुपए रेट आया है। ऑपरेटर को प्रतिदिन 180 किमी बस चलाना होगी। इसमें इलेक्ट्रिक बस, ड्राइवर, कंडक्टर और मेंटेनेंस की जिमेदारी संबंधित कंपनी की ही रहेगी। सरकार केवल प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसे भुगतान करेगी। इसके लिए केन्द्र सरकार प्रति किलोमीटर के अनुसार 22 रुपए देगी। केन्द्र सरकार यह राशि 12 साल तक देगी। इसके अलावा जो राशि बचेगी वह किराए से कवर होगी

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008